

डॉ सरफराज अंसारी ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

दैनिक बुद्ध का सन्देश

शोहरतगढ़ / सिद्धार्थनगर।

शोहरतगढ़ स्थित डॉ अंसारी

हॉस्पिटल के सर्जन मोहम्मद

सरफराज अंसारी ने क्षेत्र में

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर

लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी

प्रामाण्य दिया है। बुद्धवार को

बमनी चौराहे पर लगाये गये

स्वास्थ्य शिविर में लगभग 300

लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर

निरुशुल्क दवाइयों के साथ

डॉक्टरों से परामर्श का लाभ

लिया है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

में बमनी चौराहे से सटे आधा

दर्जन से अधिक गाँव भपसी,

भटमला, बनगावा, डबरा, लमुईया,

हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने

ने बताया कि शिविर में मरीजों

के लिए विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख

वजन आदि की जांच कर उन्हें

आदि मौजूद रहे।

अपने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर हजारों लोगों का

दवाइयां दी गई बमनी क्षेत्र के

लोगों से काफी सहयोग भी मिला।

सुबह 11 बजे से शाम चार बजे

तक चले शिविर में 280 लोगों

ने अपनी निशुल्क जांचें कराई

और मुफ्त दवाइयां प्राप्त की।

इस दौरान डॉ अदील, डॉ रहमत

अली नेता व समाजसेवी अलताफ

हुसैन, अमीरुल्लाह उर्फ दरोगा

भाई, मंजूर खान, महबूब, भाई,

परेज अख्तर, जफर आलम,

सुरज, अनुपा, फहीम सफीकुल्लह,

दिलीप जैसवाल, प्रधान बमनी

महबूब, बीड़ीसी मंजूर, महमूद प्रद

गान, मक्कू बाबा, हन्नान, अब्दुल

नई फलाही, इशराद अहमद,

जोहरा मेमोरियल स्कूल प्रबंधक

इमरान अली खान, मोनू शर्मा,

शिविर का लाभ उठाया है। यहीं

के लिए विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख

वजन आदि की जांच कर उन्हें

आदि मौजूद रहे।



उपचार कर चुके हैं। डॉ अंसारी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि शिविर में मरीजों ने बताया कि शिविर में मरीजों की इंसीजी, शुगर, बीपी और

रवि जैसवाल, हृदय राम वर्मा

गया है स इनके द्वारा बीट के

विगत 3 वर्षों में महिलाओं के 1098, 1076 के संबंध में महिलाओं

जोड़ा जाएगा जिसमें गांव के

प्रत्येक गांव में महिला सुरक्षा

सिद्धार्थनगर। जनपद समिति का गठन कर गांव की

महिलाओं एवं विद्युत विभाग की वाले अपराध

ों की रोकथाम एवं

पूर्व में घटित

अपराधों में सतत

मॉनिटरिंग के लिए

महिला कांस्टेबल की कुल

93 महिला बीट बनाई गई

महिला बीट बनाई गई है स

प्रत्येक थाने में क्षेत्रफल के अनुसार

4 से 7 की संख्या में महिला

नई फलाही इशराद अहमद,

जोहरा मेमोरियल स्कूल प्रबंधक

इमरान अली खान, मोनू शर्मा,

महिलाओं के प्रति होने वाले

छेड़खानी, मारपीट वह घरेलू

हिस्सा जैसे अपराधियों पर गांव

द्वारा बीट के

विगत 3 वर्षों में महिलाओं के 1098, 1076 के संबंध में महिलाओं

जोड़ा जाएगा जिसमें गांव के

प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो स

महिला बीट पुलिस अधिकारी

महिलाओं के प्रति होने वाले

फैडबैक लेती रहेंगी कि उनको

कारियों को पुलिस लाइन के

अब कोई समस्या तो नहीं है।

समाचार में कार्यशाला करके उनके

द्वारा बीट के

विगत 3 वर्षों में महिलाओं के 1098, 1076 के संबंध में महिलाओं

जोड़ा जाएगा जिसमें गांव के

प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो स

महिला बीट पुलिस अधिकारी

महिलाओं के प्रति होने वाले

छेड़खानी, मारपीट वह घरेलू

हिस्सा जैसे अपराधियों पर गांव

द्वारा बीट के

विगत 3 वर्षों में महिलाओं के 1098, 1076 के संबंध में महिलाओं

जोड़ा जाएगा जिसमें गांव के

प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो स

महिला बीट पुलिस अधिकारी

महिलाओं के प्रति होने वाले

फैडबैक लेती रहेंगी कि उनको

कारियों को पुलिस लाइन के

अब कोई समस्या तो नहीं है।

समाचार में कार्यशाला करके उनके

द्वारा बीट के

विगत 3 वर्षों में महिलाओं के 1098, 1076 के संबंध में महिलाओं

जोड़ा जाएगा जिसमें गांव के

प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो स

महिला बीट पुलिस अधिकारी

महिलाओं के प्रति होने वाले

छेड़खानी, मारपीट वह घरेलू

हिस्सा जैसे अपराधियों पर गांव

द्वारा बीट के

विगत 3 वर्षों में महिलाओं के 1098, 1076 के संबंध में महिलाओं

जोड़ा जाएगा जिसमें गांव के

प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो स

महिला बीट पुलिस अधिकारी

महिलाओं के प्रति होने वाले

फैडबैक लेती रहेंगी कि उनको

कारियों को पुलिस लाइन के

अब कोई समस्या तो नहीं है।

समाचार में कार्यशाला करके उनके

द्वारा बीट के

विगत 3 वर्षों में महिलाओं के 1098, 1076 के संबंध में महिलाओं

जोड़ा जाएगा जिसमें गांव के

प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो स

महिला बीट पुलिस अधिकारी

महिलाओं के प्रति होने वाले

फैडबैक लेती रहेंगी कि उनको

सम्पादकीय

स्पष्ट है कि अफगानिस्तान को लेकर बाइडन सरकार से गलती हुई है। आज उसकी इस गलती की कीमत 3.3 करोड़ अफगानियों को चुकानी पड़ रही है, जिन्हें मध्ययुगीन दौर में धकेला जा रहा है। आगे चलकर अमेरिका की यह गलती दुनिया पर भी भारी पड़...

तालिबान विद्रोही काबुल के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें राजधानी का नियंत्रण शांतिपूर्ण तरीके से सौंप दिया जाए। अजीब बात है कि तालिबान का अफगानिस्तान पर करीब-करीब कब्जा हो चुका है, जबकि अमेरिका के सैनिकों को वापस बुलाने की समयसीमा खत्म होने में अभी दो हफ्ते का वक्त बचा है। वैसे, अमेरिका 31 अगस्त की डेढ़लाइन से पहले ही अपने ज्यादातर सैनिकों को वापस बुला चुका है। अफगानिस्तान एक सदी से दुनिया की महाशक्तियों की जोर-आजमाइश के केंद्र में रहा है और सबकी आखिरकार यहां हार हुई। अस्सी के दशक के आखिर में सोवियत संघ के बाद अब अमेरिका की यहां हार हुई है। शीत युद्ध के दौर में जिन मुजाहिदीनों को अमेरिका ने सोवियत सेना से लड़ने के लिए खड़ा किया था, आज उन्हीं के हाथों उसकी शिकस्त हुई है। इस पर बहस चलती रहेगी कि क्या यह हार उसके लिए वियतनाम से बड़ी है या नहीं, लेकिन यहां उसने एक ऐसी गलती की है, जिसे लेकर उससे सवाल पूछे जाते रहेंगे। अमेरिका असल में अफगानिस्तान के जमीनी हालात का अंदाजा लगाने में बिल्कुल नाकाम रहा। इस सिलसिले में राष्ट्रपति जो बाइडन का 8 जुलाई का बयान गौरतलब है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने का मतलब यह नहीं है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो ही जाए। वह मानते थे कि अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल के तीन लाख जवान 75 हजार तालिबान विद्रोहियों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं।

उसने पिछले 20 वर्षों में इन सैनिकों की ट्रेनिंग, हथियार और वेतन देने पर 83 अरब डॉलर की रकम खर्च की थी। यह सब बताते वक्त बाइडन अफगान सेना की कमियों से मुंह चुरा गए। सच यह है कि इसके कमांडर भ्रष्ट थे। इसके जवानों का मनोबल ऐसा नहीं था कि वे तालिबान विद्रोहियों के सामने टिक पाएं। इसलिए जब एक के बाद एक शहरों में तालिबान विद्रोही घुसने लगे तो अफगान जवान बिना लड़े वहां से भाग लिए, जबकि उनके पास कहीं अधिक आधुनिक हथियार थे। कमांडरों के भ्रष्टाचार की बात खुद अमेरिकी जांच रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इसे रोकने और अफगान सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अमेरिका ने कुछ नहीं किया। उसने अपने कई पूर्व सैन्य अधिकारियों की सलाह नहीं मानी, जो कह रहे थे कि सैनिकों को वापस नहीं बुलाना चाहिए। इससे पहले तालिबान के साथ शांति वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने ऐसे दिखाया कि विद्रोही बदल चुके हैं। यह सुधरा हुआ तालिबान है। स्पष्ट है कि अफगानिस्तान को लेकर बाइडन सरकार से गलती हुई है। आज उसकी इस गलती की कीमत 3.3 करोड़ अफगानियों को चुकानी पड़ रही है, जिन्हें मध्ययुगीन दौर में धकेला जा रहा है। आगे चलकर अमेरिका की यह गलती दुनिया पर भी भारी पड़ सकती है क्योंकि तालिबान बदला नहीं है। क्या उसे फिर से अपनी अफगान नीति पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? अफगानिस्तान के प्रति अमेरिका और वैश्विक समुदाय की एक जिम्मेदारी है। उन्हें अपना यह दायित्व याद रखना होगा।

काबुल में तालिबान

आगे की चिंता करें

निरंतर हंगामे और शोर—शराबे के बीच संसद के मॉनसून सत्र का तय समय से पहले ही समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तल्खी आई, वह समाप्त नहीं हो रही है। हालांकि इसी सत्र के दौरान दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच दुर्लभ किस्म की एकजुटा भी दिखी। ओबीसी सूची बनाने के राज्यों के अधिकार से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में पार्टियों का भेद समाप्त हो गया था। लेकिन राज्यसभा में सत्र के आखिरी दिन इसके ठीक बाद जब सरकार इंश्योरेंस बिल लेकर आई तो विपक्ष बौखला उठा। उसका कहना था कि यह बिल लाने की बात तो तय नहीं थी।

इसके बाद विपक्षी सदस्यों की ओर से ऐसा हंगामा हुआ कि सदन में मार्शल बुलाने पड़े और फिर सदन में वह दृश्य उपस्थित हुआ, जो कभी नहीं हुआ था। अब जहां सरकार कह रही है कि विपक्षी सदस्यों ने मार्शलों के साथ मारपीट की, वहीं विपक्ष का आरोप है कि बाहरी लोगों को मार्शल की ड्रेस पहनाकर सदन में भेजा गया और उनसे विपक्षी सांसदों को पिटवाया गया। इस तरह के आरोप सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कभी एक-दूसरे पर नहीं लगाए थे। सचाई स्पष्ट करने के लिए राज्यसभा सचिवालय की ओर से आखिरी घंटे की कार्यवाही का मिनट-दर मिनट ब्योरा विडियो के रूप में पेश किया गया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी।

विपक्ष का कहना है कि सिलेक्टिव विडियो जारी किए गए हैं। दो पक्षों के बीच जब इस तरह की स्थिति बन जाए तो निष्पक्ष तस्वीर उभरने की संभावना धूमिल हो जाती है। लोकतंत्र में ऐसी स्थिति को हर हाल में टालना चाहिए। यह विपक्ष के लिए वाकई आत्मालोचना का अवसर है। पूरे सत्र के दौरान जिस तरह से वह एक मुद्दे को लेकर आसमान सिर पर उठाए रहा, वह उसकी राजनीति के लिए कितना फायदेमंद हुआ या आगे हो सकता है, इस पर भी उसे गंभीरता से सोचना चाहिए। आखिर उसका मकसद क्या था? सदन में तीखी बहस हो या हंगामा, शोर-शराबा किया जाए या कामकाज न चलने दिया जाए— इन सबके पीछे विपक्ष का उद्देश्य किसी खास मुद्दे की तरफ लोगों का ध्यान खींचना ही होता है।

अगर इस बार भी यही बात थी तो किरण ऐसी नौबत आखिर क्यों और कैसे आगई कि सदन में मार्शल बुलाने पड़े? निश्चित रूप से विपक्ष को देखना चाहिए कि उसका विरोध कब और कैसे हादों को पार करने लगा। इसका मतलब यह नहीं कि इस मामले में सत्ता पक्ष पूरी तरह पाक—साफ है। लोकतंत्र जिद से नहीं चलता। देखना पड़ता है कि कब विपक्ष के विरोध को अनदेखा करना है और कब हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ कर लेना है। विपक्ष को मना लेने की क्षमता का प्रदर्शन करने में सरकार निश्चित रूप से चूकी है। दोनों पक्ष सही सबक लें तो लोकतंत्र की आगे की यात्रा बेहतर बनाई जा सकती है।

आरक्षण पर संघ का साफ सुधारा नजरिया

दरअसल, नीरज की कामयाबी में उन्हें मिली सुविधाओं का भी योगदान है। उन्हें विदेशी कोच मिले। बायोमैक्रोनिकल विशेषज्ञ मिले। दूर तक भाला फेंकने की सामर्थ्य बढ़ाने वाली जर्मनी की महंगी मशीनें उपलब्ध हुईं। किसी खिलाड़ी को स्वर्णिम लक्ष्य के लिये तपरस्या से गुजरना पड़ता है। नीरज को जब लगा कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं में मुकाबले की ताकत जुटाने के लिये मारंसाहारी होना पड़ेगा तो उन्होंने ...

कृष्णमोहन झा

हमारे देश में आरक्षण हमेशा ही राजनीतिक दलों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा रहा है और हर राजनीतिक दल यह साबित करने में कोई कार कसर नहीं छोड़ता कि दलितों और पिछड़ी जातियों के हितों की चिंता उसे दूसरे दलों से अधिक है। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अनेक राजनीतिक दल तो आरक्षण के मुद्दे पर जब तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधने से भी नहीं चूकते जबकि आरक्षण के मुद्दे पर संघ का जो दृष्टिकोण कल था वही आज भी है। संघ ने कभी भी आरक्षण को चुनावी मुद्दा नहीं माना। किसी चुनाव में भाजपा की जीत की संभावनाओं को बलवती बनाने के लिए आरक्षण के मुद्दे पर का उसके निश्चित दृष्टिकोण से भटकाव भी देखने को नहीं मिला। यह बात अलग है कि अनेक राजनीतिक दलों ने आरक्षण को लेकर संघ के दृष्टिकोण में बदलाव के आरोप लगाने में कभी संकोच नहीं किया। यह आश्चर्य का विषय है कि हमेशा ही संविधान सम्मत आरक्षण का समर्थक होने के बावजूद संघ को कठघरे में खड़ा करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि संघ प्रमुख और सरकार्यवाह की कभी भी पलटवार करने की रणनीति अपनाने में दिलचर्पी नहीं दिखाई। हर मंच से संघ प्रमुख और सरकार्यवाह ने आरक्षण को लेकर संघ का स्पष्ट दृष्टिकोण दो वर्ष पूर्व न ई दिल्ली में आयोजित भविष्य का भारत कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर संघ के दृष्टिकोण की भली भाँति व्याख्या करते हुए कहा था कि सामाजिक विषमता को हटाकर सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने वाले संविधान सम्मत आरक्षण का संघ का पूरा समर्थन करता है। सामाजिक कारणों से समाज के एक हिस्से को हमने पिछले एक हजार साल में निर्वल बना दिया है। उनको ऊपर उठाने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक हजार की बीमारी को दूर करने के लिए अगर सौ डेढ़ सौ साल लगते हैं तो यह त्याग हमें करना ही पड़ेगा। यह हमारा कर्तव्य है। संघ प्रमुख ने भविष्य का भारत कार्यक्रम में स्पष्ट कहा था कि आरक्षण समस्या नहीं है। आरक्षण को लेकर होने वाली राजनीति असली समस्या है। आरक्षण कब तक जारी रहना चाहिए इस बारे में संघ प्रमुख ने सदैव एक ही बात कही है कि यह तय करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर छोड़ दी जानी चाहिए जिनके उत्थान के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लगभग दो वर्ष पूर्व भविष्य का भारत कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर जो विचार व्यक्त किए थे उनकी प्रासंगिकता आज भी उसी रूप में महसूस की जा सकती है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने हाल में ही

इन ई दिल्ली में आयोजित एक पुस्तक के विमोचन समारोह में इसी मुद्रे पर फिर एक बार संघ के दृष्टिकोण की विस्तार से चर्चा करते हुए आरक्षण को एक ऐतिहासिक आवश्यकता निरूपित किया है। दत्तात्रेय होसबोले ने अपने संबोधन में संघ प्रमुख के इस कथन को दोहराया कि आरक्षण तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि आरक्षण से लाभान्वित होने वाले लोग स्वयं ही इसे लेने से इंकार न कर दें। सरकार्यवाह ने कहा कि आरक्षण की सुविधा लेने से इंकार करना उन लोगों का विशेषाधिकार है जिनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जब तक समाज का एक वर्ग गैर बराबरी का अनुभव करता है तब तक आरक्षण को जारी रखना होगा। सरकार्यवाह ने बिना किसी लाग—लपेट के दो टूक लहजे में कहा कि दलितों के इतिहास के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। सरकार्यवाह जब आरक्षण को ऐतिहासिक आवश्यकता बताते हैं तब उनका आशय यही होता है कि इतिहास की गलतियों को सुधारने के लिए आरक्षण जरूरी है। गौरतलब है कि यही बात सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी भविष्य का भारत कार्यक्रम में आरक्षण के मुद्रे पर संघ का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कही थी। इसे भी एक संयोग ही माना जाना चाहिए कि जिस दिन सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले राजधानी में मेकर्स आफ मार्डन दलित हिस्ट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया उसी दिन लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया और दूसरे दिन राज्य सभा ने भी इस विधेयक का अनुमोदन कर दिया। प्रानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है यह विधेयक समाज के वंचित वर्गों की गरिमा और उनके लिए अवसर और न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है इसमें कोई संदेह नहीं कि आरक्षण को लेकर अनेक राजनीतिक दलों ने संघ पर निशान साधकर अपना राजनीतिक हित साधने का प्रयास किया है जबकि संघ ने हमेशा समाज के दलित शोषित और वंचित वर्ग के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आरक्षण की वकालत की है। संघ प्रमुख पहले ही कह चुके हैं कि आरक्षण समस्या नहीं है बल्कि आरक्षण को लेकर होने वाली राजनीति समस्या है। संघ ने आरक्षण को कभी भी चुनावों के ध्यान में रखकर आरक्षण के पक्ष में विचार व्यक्त नहीं किए। संघ के इस विचार से किसी राजनीतिक दल के असहमत नहीं होना चाहिए कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान समाज के जिन कमज़ोर वर्गों के लिए किया गया है उन्हें ही यह तय करने का अधिकार दिया जाए कि आरक्षण कब तक जारी रहना चाहिए। आरक्षण को लेकर संघ का दृष्टिकोण अपरिवर्तनीय है और विचारणीय भी।

हम कर्तई नहीं चाहते कि हताश युवा नशे और अपराध की ओर मुड़ें। अब उनमें लाखों युवा बेहतर मौकों की तलाश में पश्चिमी और अरब मुल्कों का रुख कर रहे हैं, भले ही वहां उन्हें समान नागरिकता प्राप्त न हो। क्यों नहीं राजनीतिक दल एक बृहद योजना बनाते, जिससे हमें विकास और रोजगार, दोनों मिलें हालिया इतिहास में विष्व में ऐसे कई अनुकरणीय मॉडल हैं, जिनसे हम सीख ...

गुरुबचन जगत
श्वेषम् भारत के लोग...ये वे शब्द हैं, जो कभी हमारे राष्ट्र के संस्थापकों ने देश का संविधान बनाते समय कहे थे दूसरे समय है इन्हें याद करने का। हमारे संविधान में जिस भावना के तहत लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था की गई है, यह वक्त है उसकी पुनर्स्थापना का, न कि उस पतन को ढोने का, जो आज व्याप्त है। यह समय है कर्णधाराओं से पूछने का रूप स्तुमने क्या किया और आगे मतदाताओं (ग्राम, जिल्हा, राज्य या राष्ट्रीय) के लिए क्या करना चाहते होय यह कमज़ोर लोगों की निशानी है कि कोई श्वेषज्वृत्य नेता हांक ले जाए, जबकि शतगङ्ग्य लोग चुने जानप्रतिनिधियों से सीधा ठोस नतीजे देने को कहते हैं। ऐसे लोगों को किसी नेता को महामानव की तरह पेश करने वाले जनसूचना प्रचारों से भरमाया नहीं जा सकता। न ही वह लालच एवं दुर्भवना से संचालित संस्थाओं द्वारा फूट डालने और गुमराह करने वाले दुष्प्रचार में बहती है। हमारी तरह के लोकतंत्र में नागरिकों से अपेक्षित है कि वे आपने निर्तान्त श्वेष में काम कर दियगाने वाले सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि को चुनेंगे (विधायक हो या सांसद या एक सरपंच) करते वक्त वे मानस पर किसी वंशवाच्या खुद को सर्वक्षमताशाली होने वाच्यने वाले को हावी न होने दें तलडने वाले कोई आसमान से उतरे बल्कि आम इनसान होते हैं, वे भी कर्मामियों, स्वशंका और असुरक्षा से होते हैं। हमें ज़रूरत है ऐसे स्थानीय उचुनने की, जिनके अंदर हम बतानागरिक अच्छा नेतृत्व, दूरदृष्टिका सहायता एवं मानवता वाले गुण प्रदाने समय में स्वयं विभिन्न दलों द्वारा घोषणापत्रों को पूरी तरह नहीं पढ़ा जाता है। उनका बाबाऊ, दोहराव भरा होना। और अनुभव है कि उनमें किए वादे शायद ही जाते हैं। कोई भी गौर कर सकता है। कांश मतदाता महत्वपूर्ण मुद्दों पर यान केंद्रित करने की बजाय जातिर्जम, क्षेत्रवाद, मतदान की पूर्व संधारणा किए लालचों में फंसकर अपना गुण लेता है। मतदाता को परी तज्ज्ञ

**शे और
युवा बेहतर
मूल्कों का
नागरिकता
एक बहुत
र रोजगार,
ऐसे कई
प्रीरव ...**

मीडिया अथवा सोशल मीडिया पर आना चाहिए, वह या तो बहुत कमज़ोर होता है वह है, सघन दौरे। आंखों देखे हालात आपको अथवा नगण्य। इसलिए समाज के बहुत बड़े बहुद आयाम प्रदान करते हैं और कार्य में तबके में राजनेताओं और राजनीति के प्रति तेजी लाते हैं। इन दिनों अफसर दौरों पर नहीं जाते, मंत्री तो केवल उद्घाटन या शादी या शोकसभा (भोग) में शामिल होने के लिए नमूदार होते हैं। सुशासन बनाने में एक अन्य अवयव है अधिकारियों की नियुक्तियां एवं स्थानांतरण। लेकिन इस व्यवस्था को भी पूरी तरह तोड़—मरोड़ दिया गया है, सही क्रियान्वयन और न्यायोचित व्यवस्था वजूद में होने का नतीजा है इलाकों में ब्रष्ट, नकारा अफसरों की नियुक्तियां। सूबे में वरिष्ठ पदों पर यानी कानून समुचित बहस के बाद स्वीकार—लागू होते हैं, नयी नीतियों का आगाज और बजट यहीं पास किए जाते हैं। यहां राष्ट्रीय महत्व के तमाम मुद्रे एवं विषय उठाए जाते हैं और उन पर मंथन होता है। किंतु जिस तरह जानबूझकर इस लोकतांत्रिक संस्थान में भारी बहुमत के बल पर छिपी मंशा वाले कानूनों को पास करवाया जा रहा है, वह निंदनीय है। क्या संसद की मौजूदा स्थिति भविष्य की इबारत है या फिर यह परिणामी बनने जा रही है यह वक्त ही बताएंगा। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय, वह श्युशासन या किर श्युनतम प्रशासनिक नियंत्रण... अद्यक्तम प्रशासन देने का वादा करता है। लेकिन किसी को याद है वास्तविक रूप में पिछली मर्तबा कब श्युशासन याला काल देखने को मिला था वह स्तर जिस पर ज्यादातर नागरिकों का राबता सरकार से पड़ता है, वे हैं—पुलिस, कराधान, विकास कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। सुशासन की नीव की शुरुआत मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारियों द्वारा वास्तविक धरातल पर जनता, मतदान क्षेत्र और विकास कार्यों से सीधा नाता रखकर और भागीदारी बनाने से होती है। जिस एक अन्य तरीके से इसे किया जा सकता है, वह है, सघन दौरे। आंखों देखे हालात आपको तबके में राजनेताओं और राजनीति के प्रति बनी विश्वास से व्यवस्था से पूरी तरह मोहर्भंग होने की स्थिति बन गई है। यहां तक कि चुनाव उपरान्त, संसद, जो कि लोकतंत्र का ढांचा है, उसका रूप धीरे—धीरे ऐसे स्वांग में तबदील कर दिया गया है कि प्रस्तुत नये कानून ज्यादातर बिना यथेष्ट बहस करवाए, केवल ध्वनि मत के जरिए स्वीकार एवं लागू करवा लिए जाते हैं। जबकि संसद ऐसा संस्थान है, जहां पेश किए जाने वाले नये कानून समुचित बहस के बाद स्वीकार—लागू होते हैं, नयी नीतियों का आगाज और बजट यहीं पास किए जाते हैं। यहां राष्ट्रीय महत्व के तमाम मुद्रे एवं विषय उठाए जाते हैं और उन पर मंथन होता है। किंतु जिस तरह जानबूझकर इस लोकतांत्रिक संस्थान में भारी बहुमत के बल पर छिपी मंशा वाले कानूनों को पास करवाया जा रहा है, वह निंदनीय है। क्या संसद की मौजूदा स्थिति भविष्य की इबारत है या फिर यह परिणामी बनने जा रही है यह वक्त ही बताएंगा। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय, वह श्युशासन या किर श्युनतम प्रशासनिक नियंत्रण... अद्यक्तम प्रशासन देने का वादा करता है। लेकिन किसी को याद है वास्तविक रूप में पिछली मर्तबा कब श्युशासन याला काल देखने को मिला था वह स्तर जिस पर ज्यादातर नागरिकों का राबता सरकार से पड़ता है, वे हैं—पुलिस, कराधान, विकास कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। सुशासन की नीव की शुरुआत मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारियों द्वारा वास्तविक धरातल पर जनता, मतदान क्षेत्र और विकास कार्यों से सीधा नाता रखकर और भागीदारी बनाने से होती है। जिस एक कोविड महामारी या नोटबंदी की पूर्व सूचना ताकि अफरातफरी और पलायन जैसे हालात न बनें। क्यों नहीं हमें देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी के आंकड़े दिए जाते एक तरफ तो हम गंगा में बहती लाशें और किनारों पर दफन मुर्दां के दृश्य देखते हैं वहीं सरकारें इन्हें नकार रही होती हैं। केंद्र सरकार कोविड से हुई कुल मौतों की जो गिनती बताती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित एजेंसियों के मुताबिक आधिकारिक आंकड़ों से वास्तविक स्थिति 10 गुणा ज्यादा है। पेगासस जासूसी प्रकरण का जिन्न बाहर निकला और निशाने पर रहे कुछ नाम भी सामने आ आए, परंतु सरकार के मुंह से एक लपज न निकला। आज सड़कों पर हजारों किसान भीषण सर्दी—गर्मी के बावजूद आंदोलनरत हैं, सैकड़ों की मौत हुई है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से एक भी मिलने नहीं गया! चाहे करतूतें केंद्र सरकार की हों या राज्यों की, सूची अंतहीन है। क्या सूचना का अधिकार अभी भी जिंदा है नागरिक चाहते हैं महत्वपूर्ण विषयों पर पारदर्शिता बने, चाहे सत्ता में कोई भी दल हो। सरकारें पर्दे में रहकर काम न करें और पूछे जाने वाले हर सवाल को देशद्रोह न ठहराया जाए। जीवनस्तर में निरंतर सुधार हो, यह चाहे हर नागरिक को होती है। अमेरिकी संविधान में तो सरकार प्रदत्त श्युशी का लक्ष्य पानाय प्रत्येक नागरिक का अधिकार बताया गया है। हमारे पूर्वजों ने भी भारतीय संविधान बनाते वक्त यहीं भावना रखी थी, जब उन्होंने सबके लिए श्युशी अवसर एवं रुतबेय की बात कही थी। रोजगार पाने का अधिकार इस घोषणा का जरूरी हिस्सा है। लोगों की रुचि आंकड़ों में नहीं है। वे सड़कों पर घूमते लाखों बेरोजगार युवा और भूखे शिशु एवं कुपोषित माओं वाली दृश्यावली देखना नहीं चाहते।

पारदर्शी व्यवस्था में सुशासन की जवाबदेही

माड़या अथवा साशल माड़या पर आना चाहिए, वह या तो बहुत कमजोर होता है अथवा नगर्ण्य। इसलिए समाज के बहुत बड़े तबके में राजनेताओं और राजनीति के प्रति बनी विश्वास से व्यवस्था से पूरी तरह मोहभंग होने की स्थिति बन गई है। यहां तक कि चुनाव उपरांत, संसद, जो कि लोकतंत्र का ढाँचा है, उसका रूप धीरे-धीरे ऐसे स्वांग में तबदील कर दिया गया है कि प्रस्तुत नये कानून ज्यादातर बिना यथेष्ट बहस करवाए, केवल धनि मत के जरिए स्वीकार एवं लागू करवा लिए जाते हैं। जबकि संसद ऐसा संस्थान है, जहां पेश किए जाने वाले नये कानून समुचित बहस के बाद स्वीकार-लागू होते हैं, नयी नीतियों का आगाज और बजट यहीं पास किए जाते हैं। यहां राष्ट्रीय महत्व के तमाम मुद्दे एवं विषय उठाए जाते हैं और उन पर मंथन होता है। किंतु जिस तरह जानबूझकर इस लोकतांत्रिक संस्थान में भारी बहुमत के बल पर छिपी मंशा वाले कानूनों को पास करवाया जा रहा है, वह निदनीय है। क्या संसद की मौजूदा स्थिति भविष्य की इबारत है या फिर यह परिपाठी बनने जा रही है यह वक्त ही बताएगा। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय, वह शुशासनन्य या फिर श्न्यूनतम प्रशासनिक नियंत्रण... अधिकतम प्रशासनन्य देने का वादा करता है। लेकिन किसी को याद है वास्तविक रूप में पिछली मर्तबा कब शुशासनन्य वाला काल देखने को मिला था वह स्तर जिस पर ज्यादातर नागरिकों का राबता सरकार से पड़ता है, वे हैं—पुलिस, कराधान, विकास कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। सुशासन की नीव की शुरुआत मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारियों द्वारा वास्तविक धरातल पर जनता, मतदान क्षेत्र और विकास कार्यों से सीधा नाता रखकर और भागीदारी बनाने से होती है। जिस एक

वह कावाड महामारा या नाटबदा का पूर्व सूचना ताकि अफरातफरी और पलायन जैसे हालात न बनें। क्यों नहीं हमें देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी के आंकड़े दिए जाते एक तरफ तो हम गंगा में बहती लाशें और किनारों पर दफन मुर्दां के दृश्य देखते हैं वहीं सरकारें इन्हें नकार रही होती हैं। केंद्र सरकार कांविड से हुई कुल मौतों की जो गिनती बताती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित एजेंसियों के मुताबिक आधिकारिक आंकड़ों से वास्तविक स्थिति 10 गुणा ज्यादा है। पेगासस जासूसी प्रकरण का जिन्न बाहर निकला और निशाने पर रहे कुछ नाम भी सामने आ आए, परंतु सरकार के मुंह से एक लपज न निकला। आज सड़कों पर हजारों किसान भीषण सर्दी-गर्मी के बावजूद आंदोलनरत हैं, सैकड़ों की मौत हुई है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से एक भी मिलने नहीं गया! चाहे करतूतें केंद्र सरकार की हों या राज्यों की, सूची अंतहीन है। क्या सूचना का अधिकार अभी भी जिंदा है नागरिक चाहते हैं महत्वपूर्ण विषयों पर पारदर्शिता बने, चाहे सत्ता में कोई भी दल हो। सरकारें पर्दे में रहकर काम न करें और पूछे जाने वाले हर सवाल को देशद्रोह न ठहराया जाए। जीवनस्तर में निरंतर सुधार हो, यह चाह हर नागरिक को होती है। अमेरिकी संविधान में तो सरकार प्रदत्त शख्शी का लक्ष्य पानाय प्रत्येक नागरिक का अधिकार बताया गया है। हमारे पूर्वजों ने भी भारतीय संविधान बनाते वक्त यही भावना रखी थी, जब उन्होंने सबके लिए इसमान अवसर एवं रुतबेय की बात कही थी। रोजगार पाने का अधिकार इस घोषणा का जरूरी हिस्सा है। लोगों की रुचि आंकड़ों में नहीं है। वे सड़कों पर घूमते लाखों बेरोजगार युवा और भूखे शिशु एवं कृपोषित मांओं वाली दृश्यावली देखना नहीं चाहते।

न्यायालीश ने जिला कारागार का किया निरीक्षण

देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व न्यायालीश आरिक निसामुनीने मंगलवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने कारागार में निरुद्ध बंदियों के बारे में जानकारी ली। कहा कि कोरोना को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के हाई पावर कमेटी की तरफ से दिए गए आदेश का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। परिसर को निरंतर सेनिटाइज किया जाना चाहिए। निरुद्ध कैदियों को शारीरिक दूरी का पालन कराएं। हाथों को साबुन से धोने व हमेशा मुंह को मास्क से ढकने का निर्देश दिया। कैदियों के लिए मीन्च के अनुसार पौष्टिक आहार की व्यवस्था करें। कारागार परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। कैदियों को कोरोनारोधी टीका लगवाएं। महिला बैरक में साथ रहने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ दूध की व्यवस्था कराएं। न्यायालीश ने जेल में स्थापित लीगल ऐड क्लीनिक का निरीक्षण किया। कहा कि यदि किसी बंदी को विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकता है। यदि किसी बंदी को अपने मामले में ऐरेंसी की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निश्चुल अधिवक्ता प्राप्त कर विधिक सहायता ले सकता है। डिएमी जेलर के केंद्रीकृत, वन्दना त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता गिरिजेश शाही, मनोज विष्णुकर्मा, राजू यादव आदि मौजूद रहे।

शिक्षकों की समस्याओं को लेकर विचार-विमर्श

देवरिया। उप्र जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ की बैठक सदर बीआरसी सभागार में हुई, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं को लेकर विचार-विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर सेवानिवृत्त 73 शिक्षकों व कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले शिक्षकों के स्वजन को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी व महामंत्री नरेंद्र कौशिक की मौजूदगी रही। जिला महामंत्री नदलाल ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्धारित प्रारूप पर फैशन स्टीर्कर्ट अधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा कि चयन वेतनमान से संबंधित पत्रावलियों के निस्तारण में देरी की जा रही है। पुरानी फैशन बहाली के मुद्दे पर प्रदेश संगठन के बारे में बातें बताएं और उनका कर ठोक रखें। रुद्रपुर के अध्यक्ष राकेश ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों के अवश्यक संपूर्ण वेतन का भुगतान एक साथ नहीं चाहिए। बैठक में अशक्त अली खां, हेमंत शुक्ला, जयदीप सिंह, बैठक कुमार, ओमप्रकाश कुशवाहा, सुनीता सिंह, रामायी यादव, हरेराम यादव, अमरनाथ वर्मा, दीनदयाल, बालेन्दु मिश्रा आदि मौजूद रहे।

सरांफा की दुकान का ताला तोड़ जेवर
सहित तिजोरी उठा ले गए चोर

देवरिया। थाना क्षेत्र के गुलहरिया चौराहे स्थित सरांफा की दुकान का शटर तोड़कर सोमवार की रात चोरों ने तिजोरी सहित अच्युत अच्युत की भाँति वे अपनी दुकान को बंद करके घर चले गए। देर रात चोर दुकान की शटर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। चोर, दुकान में रहे तिजोरी को ही उठा ले गए। सुबह तिजोरी मठिया खरीद गांव में जाने वाली सुकून के किनारे एक खेत में दूटी हालत में मिली। दुकानदार का कहना है कि तिजोरी में 30 हजार रुपये नकद, 13 अदद सोने की कीमत, 23 अदद लरी समेत सोने की निधियां, 17 ग्राम पुराना सोना, ग्राहक का गिररी रखा एक सोने का चेन, चार किलो चांदी, चांदी के पायल रखा हुआ था जिसे चोर उठा ले गए। इंस्पेक्टर जायंत सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। शीघ्र ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

अमन-वैन में खलल बर्दाशत नहीं

देवरिया। स्थानीय थाना परिसर में पीस कमटी की बैठक हुई। जिसमें त्योहारों को लेकर नागरिकों के साथ रणनीति बनाई गई। क्षेत्राधिकारी पंचम लाल ने कहा कि मोहर्रम अच्युत त्योहार कोविड प्रोटोकाल के तहत मनाया जायेगा। शांति व्यवस्था में खलल पैदा करने वालों से पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा। कहा कि ताजिया जुलूस नहीं निकलेगा। सबको शासन के निर्देश के अनुसार घर पर ही मोहर्रम मनाना है। न्यायाली चंद्रमान सिंह ने कहा कि शासन व उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। किसी को स्थानीय स्तर पर कोई भी दिक्कत हो तो वह थाने से संपर्क कर सकता है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा के दृष्टि से सदैव तत्पर हैं। एसआइ अशुतोष कुमार, एसआइ संतोष कुमार, एसआइ राणजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, रविद्र यादव, सुनील कुमार, मुंशी दीपक नायक, मुंशी रामशीष, शुभम सिंह अतुलनाथ, शामी म., इद्रीश, नरी, अमीर मास्टर, सलामुदीन, सोबराती अंसारी, सुहेल, निजामुदीन अंसारी, मुनीब अंसारी, यासीन अंसारी आदि मौजूद रहे।

कोतवाली पुलिस के हथे चढ़ा

10 हजार का इनामी बदमाश

देवरिया। वार्षित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चाला गए ए अभियन के तहत कोतवाली पुलिस ने पिपरपाटी पुलिया के समीप से 10 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन असफलता हाथ लग रही थी। पुलिस को किसी ने सूचना दिया कि 10 हजार का इनामी बदमाश रघुवीर कुमार गोतम पुत्र रामनशेश प्रसाद दिवारी अंबेडकर नगर भीखमपुर रोड वार्ड नं तीन, भीखमपुर रोड से कुछ देर में गुजरेगा। कुछ ही देर में प्रभारी कोतवाल दारोगा अश्वनी सिंह, महेंद्र मोहन मिश्रा, व सिपाही दीपक यादव, विनय प्रताप यादव, रितेश सोनकर, बृजेश कन्नौजिया के साथ धेराबंदी की ओर वह जैसे ही दिखा उसे पुलिस टीम ने दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाश पर जानलेवा हमला समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उस पर पुलिस ने 10 हजार रुपये इनाम घोषित किया था। प्रभारी कोतवाल विपिन मलिक ने बताया कि बीते दिनों पोस्टमार्टम चौराहा पर एक व्यक्ति को घेर कर उसे बदमाश ने चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया था। पुलिस इसे तलाश रही थी, लेकिन यह हाथ नहीं लग रहा था।

जांच में सभी 1923 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव

देवरिया। जिले में कोरोना संक्रमण की रप्तार थम गई है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के लगातार कोरोना के प्रति लोगों की असर है जिले में दस दिनों से एक भी कोरोना मरीज नहीं मिले हैं। मंगलवार को आई कोरोना संक्रमण समाप्त हो तुला है। इसके लिए लोगों को लोगों को कोविड टेस्ट के बाद ही डाक्टर देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता की जा चुकी है। सीएमओ डा. आलोक पांडेय ने कहा कि जिले में भले विभाग उसे समाप्त करने पर भी कोरोना संक्रमण कोविड में 1923 लोगों की जांच रिपोर्ट में 19994 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड नियमों का पालन हर हाल में करें। संक्रमण कहाँ से शुरू हो जाएगा नहीं कहा जा सकता है। यह महामारी है इससे 218 लोगों की मौत हुई है। 24 बचाव जरूरी है।

10126 लोगों को लगाया गया

कोरोनारोधी टीका

जिले में कोरोना संक्रमण की

रप्तार कम करने के बाद अब

प्रतिवर्ष ने कहा कि जिले में भले

विभाग उसे समाप्त करने पर

तुला है। इसके लिए लोग स्वास्थ्य

विभाग अधिक से अधिक लोगों

को कोरोनारोधी टीका लगाया

गया। लगावाने के लिए लोग स्लाट

कोरोनारोधी टीका लगवाने के लिए भले

नहीं बुक कर पाए रहे हैं। स्लाट

कोरोनारोधी टीका लगाने का समय

लक्ष्य रखा गया था। 18 वर्ष से

नहीं पता चल पाए रहा है। जिससे

45 वर्ष तक 6496 लोगों को

लोगों को देखा गया। 45 से 60 वर्ष

कोरोनारोधी टीका लगाने के लिए भले

से 1621 को प्रथम व

संख्या में लोग पहुंच रहे हैं लेकिन

662 को द्वितीय डोज दिया गया।

सभी लोगों को टीका नहीं लग

60 वर्ष से उपर 548 को प्रथम

पर रहा है। मंगलवार को 63

डोज व 312 को द्वितीय डोज

प्रथम डोज व 484 को द्वितीय है।

हैं कि किसी भी तरह से कोरोनारोधी

डीएम ने कोरोनारोधी

टीकाकरण का लिया जायजा

जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोनारोधी टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी ली। डीएम ने कतार में खड़े लोगों से टीकाकरण के बारे में पूछा कि इस मामले में किसी कर्मचारी ने धन उगाई तो नहीं की।

भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, महिलाओं के तोक्यो पैरालम्पिक के लिये रवाना लिए 20 साल की प्रगति रातों-रात गायब हुई

नयी दिल्ली। भारतीय दल को विदाई देने इंदिरा गांधी चंद और विनोद कुमार भी इस दल में शामिल थे।

पीसीआई अध्यक्ष दीपा मलिक ने इस मौके पर कहा, "पूरा देश, माननीय प्रधानमंत्री और खेलमंत्री आज हमारी हॉस्टल अफजाई कर रहे हैं। पैरालम्पिक जा रहा है खिलाड़ी पहले ही से विजेता है। मैं उन्हें शुभकामना देती हूं।"

बीलीचेर पर जा रहे खिलाड़ियों को पहली बार

स्वर्णम इडिया ने विशेष वाहन

मुहूर्या करारेंससे उनका

आवागमन आसान हो गया।

इसे रेखांडी से आये टेक चंद

और नोएडा से आई मलिक

ने इस्टेमाल किया। भारत

का दूसरा दल बुधवार की

शाम को रवाना होगा जिसमें

पीसीआई अध्यक्ष समेत 14 लोग

होंगे और भारत 25 अगस्त को

अपने अभियान का आगाज करेगा।

खिलाड़ियों का पहला दल बुध वार को तोक्यो पैरालम्पिक के खेल मत्रालय, भारतीय खेल प्राप्ति लिये रवाना हो गया जिसमें भारत अग्रणी और भारतीय पैरालम्पिक के ध्वजावाहक मरियाप्पन थांगावेलु समिति के अधिकारी मोजूद थे। भी शामिल हैं। आठ सदस्यीय मरियाप्पन के अलावा टेक

काबूल। अफगानिस्तान में तालिबानियों की वापसी का पाकिस्तान

की इमरान खान सरकार ने समर्थन किया था और अब तालिबानियों को लेकर पूर्व विधायक स्वामीनाथ यादव ने बुधवार को रामजानकी मार्ग पर बरेजी पुल पर जनसमस्याओं को लेकर जाम कर दिया। करीब एक घंटे तक आवागमन ठप रहा। तहसीलदार सतीश कुमार मौके पर पहुंच जापन लिया।

जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। पूर्व विधायक यादव ने बरेजी पुल पर एप्रोच मार्ग बनाने, सतरांव मार्ग के मरम्मत करने, विद्युत तार बदलने, कपरवार रुद्रपुर, करुवान मार्ग बनाने, मोहन सिंह सेतु का कार्य जल्द पूर्ण करने की मांग को लेकर जाम कर धरना किया। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के निहित के कार्यों को कराने में विफल रही है। रमाशंकर गुप्त, जय प्रकाश सिंह, हरराम चौधरी, रवींद्र रावत, गुलाब लक्ष्मी रावत आदि वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद आतंकवादियों की मौजूद हो गई है। पिछले एक सप्ताह में तालिबानियों ने 2,300 आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। इन आतंकवादियों को काबूल, कंधार और बगराम जेल से रिहाई मिली है और अब पाकिस्तान भी तालिबान के समर्थकों को रिहा कर रहा है। गौरतलब है कि इमरान खान तालिबान द्वारा काबूल पर नियंत्रण किए जाने का समर्थन करते हुए दिखे और उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अफगानिस्तान में लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष रविवार को उस समय चरम पर पहुंच गया जब तालिबान ने काबूल में प्रवेश किया और राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया।

रिहा कर दिया है। पिछले पांच सालों से मुल्ला मोहम्मद रसूल को

पाकिस्तान की जेल में कैद था लेकिन अब उसे आजाज कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान से अलग होने के बाद मुल्ला मोहम्मद रसूल ने अपना अलग संगठन बना लिया था। जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे हिसात में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद आतंकवादियों की मौजूद हो गई है। पिछले एक सप्ताह में तालिबानियों ने 2,300 आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। इन आतंकवादियों को काबूल, कंधार और बगराम जेल से रिहाई मिली है और अब पाकिस्तान भी तालिबान के समर्थकों को रिहा कर रहा है। गौरतलब है कि इमरान खान तालिबान द्वारा काबूल पर

नियंत्रण किए जाने का समर्थन करते हुए दिखे और उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अफगानिस्तान में लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष रविवार को

उस समय चरम पर पहुंच गया जब तालिबान ने काबूल में प्रवेश किया और राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया।

रिहा कर दिया है। पिछले पांच सालों से मुल्ला मोहम्मद रसूल को

पाकिस्तान की जेल में कैद था लेकिन अब उसे आजाज कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान से अलग होने के बाद मुल्ला मोहम्मद रसूल ने अपना अलग संगठन बना लिया था। जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे हिसात में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद आतंकवादियों की मौजूद हो गई है। पिछले एक सप्ताह में तालिबानियों ने 2,300 आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। इन आतंकवादियों को काबूल, कंधार और बगराम जेल से रिहाई मिली है और अब पाकिस्तान भी तालिबान के समर्थकों को रिहा कर रहा है। गौरतलब है कि इमरान खान तालिबान द्वारा काबूल पर

नियंत्रण किए जाने का समर्थन करते हुए दिखे और उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अफगानिस्तान में लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष रविवार को

उस समय चरम पर पहुंच गया जब तालिबान ने काबूल में प्रवेश किया और राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया।

रिहा कर दिया है। पिछले पांच सालों से मुल्ला मोहम्मद रसूल को

पाकिस्तान की जेल में कैद था लेकिन अब उसे आजाज कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान से अलग होने के बाद मुल्ला मोहम्मद रसूल ने अपना अलग संगठन बना लिया था। जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे हिसात में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद आतंकवादियों की मौजूद हो गई है। पिछले एक सप्ताह में तालिबानियों ने 2,300 आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। इन आतंकवादियों को काबूल, कंधार और बगराम जेल से रिहाई मिली है और अब पाकिस्तान भी तालिबान के समर्थकों को रिहा कर रहा है। गौरतलब है कि इमरान खान तालिबान द्वारा काबूल पर

नियंत्रण किए जाने का समर्थन करते हुए दिखे और उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अफगानिस्तान में लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष रविवार को

उस समय चरम पर पहुंच गया जब तालिबान ने काबूल में प्रवेश किया और राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया।

रिहा कर दिया है। पिछले पांच सालों से मुल्ला मोहम्मद रसूल को

पाकिस्तान की जेल में कैद था लेकिन अब उसे आजाज कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान से अलग होने के बाद मुल्ला मोहम्मद रसूल ने अपना अलग संगठन बना लिया था। जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे हिसात में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद आतंकवादियों की मौजूद हो गई है। पिछले एक सप्ताह में तालिबानियों ने 2,300 आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। इन आतंकवादियों को काबूल, कंधार और बगराम जेल से रिहाई मिली है और अब पाकिस्तान भी तालिबान के समर्थकों को रिहा कर रहा है। गौरतलब है कि इमरान खान तालिबान द्वारा काबूल पर

नियंत्रण किए जाने का समर्थन करते हुए दिखे और उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अफगानिस्तान में लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष रविवार को

उस समय चरम पर पहुंच गया जब तालिबान ने काबूल में प्रवेश किया और राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया।

रिहा कर दिया है। पिछले पांच सालों से मुल्ला मोहम्मद रसूल को

पाकिस्तान की जेल में कैद था लेकिन अब उसे आजाज कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान से अलग होने के बाद मुल्ला मोहम्मद रसूल ने अपना अलग संगठन बना लिया था। जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे हिसात में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद आतंकवादियों की मौजूद हो गई है। पिछले एक सप्ताह में तालिबानियों ने 2,300 आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। इन आतंकवादियों को काबूल, कंधार और बगराम जेल से रिहाई मिली है और अब पाकिस्तान भी तालिबान के समर्थकों को रिहा कर रहा है। गौरतलब है कि इमरान खान तालिबान द्वारा काबूल पर

नियंत्रण किए जाने का समर्थन करते हुए दिखे और उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अफगानिस्तान में लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष रविवार को

उस समय चरम पर पहुंच गया जब तालिबान ने काबूल में प्रवेश किया और राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया।

रिहा कर दिया है। पिछले पांच सालों से मुल्ला मोहम्मद रसूल को

जानिए कैसे की जाती है बैटल रोप एक्सरसाइज और इससे जुड़ी कुछ खास बातें



बैटल रोप एक तरह की कार्डियो एक्सरसाइज है जिसे रसिंयों की मदद से किया जाता है। बैटल रोप एक्सरसाइज में इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी 30 मीटर लंबी और 1.5 इंच चौड़ी से लेकर 100 मीटर लंबी और 2.5 मीटर तक चौड़ी होती है। अगर आप रोजाना इस एक्सरसाइज को करते हैं तो इससे आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। आइए आज आपको इस एक्सरसाइज को करने का तरीका और इससे जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं।

बैटल रोप एक्सरसाइज करने का तरीका: सबसे पहले जमीन पर एडियों के बल खड़े हो जाएं। इसके बाद रस्सी के दोनों सिरों को दोनों हाथों में पकड़ें। अब अपने शरीर को आगे की ओर थोड़ा झुकाएं और ध्यान रखें कि शरीर पीछे की ओर जारा सा भी न झुकें। इसके बाद रसिंयों को उछालकर इनसे टेढ़ी—मेढ़ी तररों (दब्ब 5डब्ब 2डब्ब 1दग्हा) बनाएं। धीरे—धीरे रस्सी उछालने की गति बढ़ाएं और तेजी से बैटल रोप करें। कुछ मिनट इस एक्सरसाइज को लगातार करके बंद करें।

सावधानियाः एक्सरसाइज के दौरान जरूर बरतें ये सावधानियाः

इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ मिनट ठीक डंग से वार्मअप जरूर करें। शुरुआत में बैटल रोप एक्सरसाइज को एक जिम ट्रेनर के सामने करें। अगर आपको हाथ—पैर, पीठ या फिर सीने में दर्द है तो इस एक्सरसाइज को करने से बचें। अपनी क्षमता से अधिक वजन की रस्सी न उठाएं। गर्भवती महिलाओं को भी यह एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आप अर्थाराइटिस से ग्रस्त हैं तो भी इस एक्सरसाइज को न करें।

फायदे: रोजाना बैटल रोप एक्सरसाइज करने के फायदे

इस एक्सरसाइज का शरीर की हवदय वाहिनियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक्सरसाइज शरीर में जमे अतिरिक्त वसा को कम करने में मदद कर सकती है। यह एक्सरसाइज शरीर की सभी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक है। इस एक्सरसाइज से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और इससे शरीर में लचीलापन भी आता है। यह एक्सरसाइज एक बैटरीन एनर्जी बूस्टर है।

एक्सरसाइज से जुड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी

इस एक्सरसाइज को करते समय रस्सी के सिरों को अच्छी तरह से और एकदम टाइट पकड़ें। एक्सरसाइज के दौरान रस्सी से तरंग बनाने के लिए बाहों की बजाय कंधों का अधिक इस्तेमाल करें। बैटल रोप का अभ्यास करते समय सामान्य रुप से सांस लेते रहें। इस एक्सरसाइज को करते समय अपने सिर और कूलों पर अधिक धबाव न लालें। एक्सरसाइज के दौरान अपनी गर्दन को जकड़ें नहीं, बल्कि इसे सामान्य रखें।

बिंग बॉस 15 के ओटीटी संस्करण से बाहर होने वाली पहली प्रतिभागी बनी उर्फ़ जावेद

टीवी शो बिंग बॉस की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। यह शो अपने विवादों और गाँधीजप के लिए जाना जाता है। बिंग बॉस



टाइगर 3 की शूटिंग के लिए जल्दी रुस रवाना होंगे सलमान और कैटरीना



सलमान खान और कैटरीना कैफ पिछले काफी समय से फिल्म टाइगर 3 को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है और हो भी क्यों ना, इस फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल जो मचाया है। अब दोनों जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय चरण की शूटिंग के लिए रुस रवाना होंगे। फिल्म को बड़े स्तर पर शूट करने की योजना बनाई गई है।

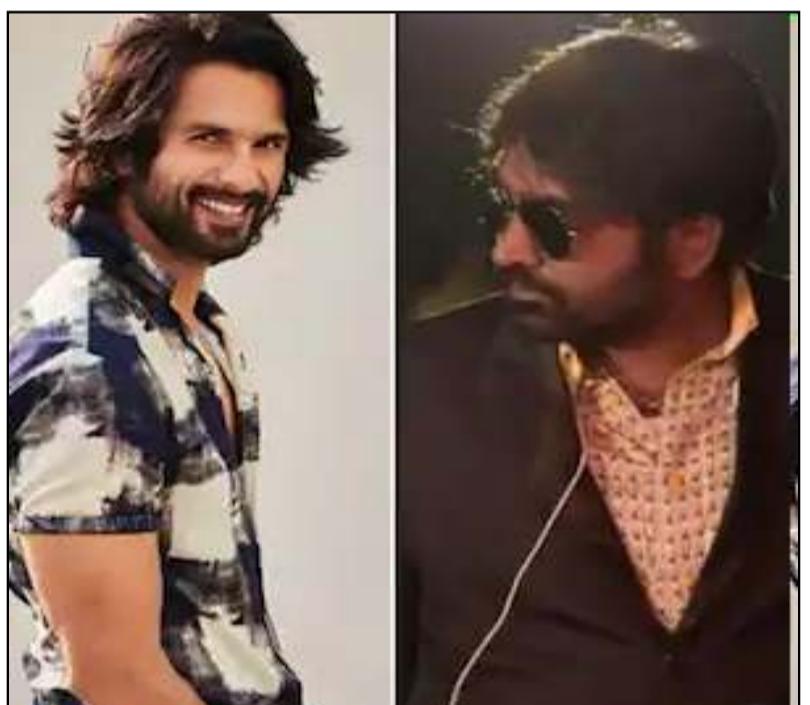
रिपोर्ट के मुताबिक सलमान और कैटरीना टाइगर 3 की शूटिंग के लिए 18 अगस्त को रुस जाएंगे, जहां फिल्म का करीब 45 दिनों का शेंजूल रहेंग। रुस के अलावा सलमान—कैटरीना कुल पांच अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों में फिल्म की शूटिंग करेंगे, जिसमें ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए और यशराज फिल्म्स ने सुरक्षा का खास ख्याल रखा है और इसलिए वह अपनी टीम को एक जबो चार्टर के माध्यम से रुस लेकर जाएंगे।

निर्देशक मनीष शर्मा इस शेंजूल के लिए पिछले कुछ महीनों से तैयारी कर रहे थे, वहीं, आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि टाइगर 3 का अंतर्राष्ट्रीय शेंजूल बिना किसी रुकावट के पूरा हो। सूत्र ने आगे बताया कि इस शेंजूल के लिए सलमान और कैटरीना सबसे पहले रुस में खतरनाक एक्शन सीक्रेट्स की शूटिंग करेंगे, जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। उसके बाद वे तुर्की और ऑस्ट्रिया रवाना होंगे। फिल्म में कई आकर्षक विज्ञान फिल्म की देखने को मिलेंगे।

टाइगर फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म एक था टाइगर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झाड़े गड़ दिए थे। इस फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया था। इसके बाद 2017 में प्राइम टाइगर जिंदा है रिलीज हुई थी। यह भी सुपरहिट हुई थी। टाइगर 3 इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। पहली दो फिल्मों की तर्ज पर उम्मीद है कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करेगी। यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनने जा रही है।

सलमान फिल्म कभी इद कभी दिवाली में पूजा होगड़े के साथ स्क्रीन शेर्यर करते दिखेंगे। वह फिल्म पठान का भी हिस्सा है। सलमान रेस 4 में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। दूसरी तरफ कैटरीना, अक्षय कुमार के साथ फिल्म सूर्यवंशी में नजर आएंगी। वह फोन भूत में काम कर रही है। कैटरीना निर्देशक जोया अख्तार की अगली फिल्म को लेकर भी चर्चा में है। वह साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति अभिनीत फिल्म मेरी क्रिसमस से भी जुड़ी हैं।

वेब सीरीज में शाहिद कूपर के साथ नजर आएंगे विजय सेतुपति



विजय सेतुपति दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार माने जाते हैं। सेतुपति को बड़ी संख्या में पूरे देश में प्रशंसक प्रसंद करते हैं। अब जानकारी सामने आ रही है कि वह बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कूपर के साथ अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज में नजर आएंगे। वह राज निदिमोल और कृष्ण डीके की सीरीज में दिखेंगे। राज और डीके ने इस संबंध में रविवार को पुष्टि की है कि उनके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा सेतुपति बन गए हैं।

इस प्रोजेक्ट के लीड कलाकार शाहिद ने भी सोशल मीडिया पर सेतुपति के साथ काम करने को लेकर अपनी उत्पुक्ता व्यक्त की है। शाहिद इस अन्टाइटल वेब सीरीज से डिजिटल स्टेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाले हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, सेट पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक्टर सेतुपति के साथ फ्रेम साझा करने का इंतजार नहीं कर सकता। राज खन्ना, मुझे सेट पर आपके साथ रहने की आदत हो गई है।

इस सीरीज में अभिनेत्री राशि भी नजर आएंगी। राशि ने इससे पहले सेतुपति के साथ दो बॉलीवुड में अधिक एक्शन फिल्म वीडियो पर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा। वह उनके साथ आगामी प्रोजेक्ट तुगलक दरबार में भी नजर आएंगी। राशि ने भी सेट पर सेतुपति का स्वागत किया है। उन्होंने अपने ट्रिवटर पोस्ट में लिखा, मैं तीसरी बार अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ काम कर रही हूँ, इस बार हिंदी में।

राज और डीके ने भी सोशल मीडिया पर सेतुपति के साथ अपनी तस्वीर साझा करके खुशी व्यक्त की है। इस तस्वीर में सेतुपति राज और डीके के बीच में बैठे दिखे हैं। सेतुपति राज और डीके के साथ खुशनुमा मूड में नजर आए हैं। यह एक थ्रिलर सीरीज होगी, जिसे राज और डीके द्वारा बनाया जाएगा। इस सीरीज का प्रसारण डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए शाहिद मेकर्स की पहली प्रसंद थे।

हाल में रिलीज हुई अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज मैन 2 को लेकर राज और डीके लाइम लाइट में हैं। इस सीरीज में दिग्जाज अभिनेता मनोज बाजपेही मुख्य भूमिका में दिखे थे। द फैमिली मैन 2 ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस सीरीज को सीती आर मेनन, सुमन कुमार और हुसैन दलाल ने मिलकर लिखा है। सीरीज के पहले भाग द फैमिली मैन को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी।

वायरल फीवर से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं ये चीजें

मौसम में बदलाव होते ही कई लोग वायरल फीवर यानि मौसमी बुखार की चपेट में आ जाते हैं। यह बुखार कई तरह के संक्रमण की वजह से होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अटेक करता है जिसकी वजह से शरीर में इंफेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। हालांकि कुछ चीजों का सेवन आपको इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जीजों के बारे में बताते हैं।

धनिये की चाय का करें सेवन

वायरल फीवर से राहत दिलाने में धनिये की चाय का सेवन काफी है। धनिये के बीज एंटीबायोटिक्स के साथ-साथ कई विटामिन्स से समृद्ध होते हैं जो वायरल संक्रमण से लड़ने की शक्ति देने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करने में सहायता हो सकते हैं। राहत के लिए एक गिलास पानी में एक बड़ी चम्म